* 20th Year
* Issue: 125
* 07.09.2026 (MONDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

पीएम मोदी ने एसआरसीसी में विपक्ष पर साधा निशाना, नाराज फूफा से की आलोचकों की तुलना

नयी दिल्ली ०६/०९ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्त्रष्टष्ट) के शताज़्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2013 के भारत और आज के भारत की तुलना करते हुए कहा कि देश पिछले एक दशक में आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत हुआ है और आज ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

अपने भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष और सरकार की नीतियों के आलोचकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वे हर काम पर सवाल उठाते हैं कि 卐इसकी जरूरत ज़्या है?卐 पीएम ने ऐसे आलोचकों की तुलना परिवार के उस 'नाराज फूफा' से की, जिन्हें हर चीज में कमी नजर आती है। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही थी, तब भी सवाल उठाए गए थे। इसी तरह बुलेट ट्रेन, क्क्ष्ठ, सेमीकंडज़्टर और नए संसद भवन जैसे प्रोजेज़्ट्स को लेकर भी आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि आज इन्हीं पहलों ने भारत की क्षमता और विकास की तस्वीर बदलने में योगदान दिया है। नएस्थान तलाशें

पीएम मोदी ने अपने 15 अगस्त के लाल किले के भाषण का जिक्र करते हुए 'दिमागी नज़्सल' शज़्द पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने आलोचकों को 'होज़्योपैथिक दवा' दी थी और उनके बयान के बाद कई लोगों की सोच सामने आ गई। पीएम ने इस दौरान देश के विकास को लेकर अपनी सरकार की नीतियों का बचाव किया और कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।स्त्रष्टष्ट के छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें 2013 का भारत याद करना चाहिए। उन्होंने उस समय की आर्थिक चुनौतियों, आतंकवादी हमलों और देश के सामने मौजूद दूसरी समस्याओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत पहले के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने अपनी बात रख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पिछले करीब एक दशक में लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (स्नञ्ज) किए हैं। उनके मुताबिक, नए बाजार खुलने से देश के युवाओं और कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकारीनीतियां पढ़ें

प्रधानमंत्री ने भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का असर अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है। एक अन्य संबोधन में पीएम मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2013 में भारत को 'फ्रैजाइल फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, जबकि आज देश की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर है। पीएम मोदी का स्त्रष्टष्ट से पुराना जुड़ाव रहा है। वह करीब 13 साल बाद दोबारा इस कॉलेज पहुंचे। फरवरी 2013 में गुजरात के मुज़्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्त्रष्टष्ट में छात्रों को संबोधित किया था। उस समय भी उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और विकास को लेकर अपनी सोच छात्रों के सामने रखी थी। इस बार अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को देश के भविष्य में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

पीएम मोदी ने कहा कि आज युवाओं के सपने सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे खुद कंपनियां और नए कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने युवाओं की इसी उद्यमशील सोच को भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।

सीएम विष्णुदेव साय ने झीरम घाटी हमले पर एनआईए फैसले के बाद कांग्रेस से सबूतों पर सवाल पूछे

रायपुर ०६/०९ (संवाददाता): छज़्तीसगढ़ के मुज़्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमला मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अदालत के फैसले की आलोचना को लेकर रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि पार्टी ने जांच एजेंसी को अपने दावों का कोई सबूत ज़्यों नहीं सौंपा। साय ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सच नहीं बदल सकता। जगदलपुर की एक विशेष एनआईए अदालत ने इस हमले के सिलसिले में गिरज़्तार सभी 10 आरोपियों को शनिवार को दोषी ठहराया। इस हमले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विद्याचरण शुज़्ल और महेंद्र कर्मा सहित 29 लोग मारे गए थे। अदालत ने सजा की अवधि तय करने के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है। यह घातक हमला 25 मई, 2013 को हुआ था, जब माओवादियों ने बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत

झीरम घाटी में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर घात लगाकर हमला किया था। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुज़्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ''अधूरा न्याय'' करार दिया था। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे की कथित बड़ी राजनीतिक साजिश की जांच नहीं की गई है।

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि 10 आरोपियों को दोषी ठहराया जाना बस्तर, पीड़ितों के परिवारों या कांग्रेस के साथ न्याय नहीं है। इस आलोचना का जवाब देते हुए मुज़्यमंत्री साय ने कहा कि यह मामला तब एनआईए को सौंपा गया था, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार सज़्ता में थी। मुज़्यमंत्री साय ने कहा, ''जांच और न्यायिक प्रक्रिया लगभग 13 वर्षों तक चली, सौ से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत ने सभी तथ्यों तथा सबूतों की जांच करने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 10 लोगों को दोषी ठहराया है और यह 16 सितंबर को उनकी सजा तय करेगी।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि एनआईए देश की शीर्ष जांच एजेंसी है, किसी राज्य सरकार की एजेंसी नहीं। बघेल पर तंज कसते हुए साय ने कहा कि जब कांग्रेस नेता विपक्ष में थे, तब वह दावा किया करते थे कि वह ''अपनी जेब में सबूत लेकर घूम रहे हैं।'' साय ने बघेल पर निशाना साधते हुए कहा, ''सवाल यह है कि अगर उनके पास सबूत थे, तो उन्होंने इसे एनआईए को ज़्यों नहीं सौंपा? उनके पास जांच एजेंसी के सामने तथ्यों को रखने के लिए पर्याप्त समय था।

कश्मीर, नक्सलवाद, साइबर क्राइम और ड्रग्स... अमित शाह ने बताया सुरक्षित भारत का पूरा रोडमैप

नयी दिल्ली ०६/०९ (संवाददाता): गोवा के डोना पॉला में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार की उपलज़्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के समय देश के सामने तीन बड़ी जज़्मू-कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोज़्तर में हिंसक उग्रवाद और देश के बड़े हिस्से में फैला नज़्सलवाद चुनौतियां थीं। शाह ने कहा कि इसके अलावा देश में लगातार हो रहे बम धमाके और महिलाओं की सुरक्षा भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। उनके मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में इन मोर्चों पर स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।अमित शाह ने कहा कि 2019 में जज़्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां अलगाववाद की भावना में काफी कमी आई है। उन्होंने दावा किया कि

आतंकवाद के आंकड़े लगभग शून्य की ओर बढ़ रहे हैं और घाटी में अब विकास को लेकर नया माहौल बना है। शाह ने कहा कि जज़्मू-कश्मीर में लोगों और देश के बाकी हिस्सों के बीच मानसिक दूरी कम हुई है और क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।गृह मंत्री ने कहा कि दशकों से देश के सामने चुनौती बना नज़्सलवाद अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि रेड कॉरिडोर का सपना देखने वाले कई लोगों ने हथियार छोड़कर मुज़्यधारा में लौटने का रास्ता चुना है। पूर्वोज़्तर को लेकर शाह ने कहा कि करीब 10 हजार युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही 14 से ज्यादा शांति समझौतों के जरिए क्षेत्र में शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ है।अमित शाह ने आर्थिक अपराधियों और विदेशों में छिपे भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2019 से जुलाई 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों का प्रत्यर्पण कराकर उन्हें भारतीय अदालतों के सामने लाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत-पोल नाम का एक विशेष सिस्टम तैयार किया गया है। इसके जरिए 14 से ज्यादा केंद्रीय एजेंसियां और सभी राज्यों की पुलिस आपस में जुड़ी हुई हैं। शाह के मुताबिक, इस सिस्टम के जरिए भगोड़ों की करीब 17,874 करोड़ रुपये की संपज़्ति सील की जा चुकी है।अपराध और साइबर सुरक्षा पर बोलते हुए गृह मंत्री ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन आम लोगों के लिए साइबर अपराध के खिलाफ सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रही है।शाह ने देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के सकारात्मक परिणाम मिलने का भी दावा किया। उन्होंने गोवा पुलिस का उदाहरण देते हुए कहा कि नए कानूनों के बाद राज्य की दोषसिद्धि दर 22 प्रतिशत से बढ़कर 53.2 प्रतिशत हो गई है।

पीएम मोदी के नाराज फूफा बयान पर भड़की कांग्रेस, खरगे बोले-युवा भी लेकर खड़े हैं रिपोर्ट कार्ड

नयी दिल्ली ०६/०९ (संवाददाता): दिल्ली विश्व विद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्त्रष्टष्ट) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के %नाराज फूफा% वाले बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के लिए नए-नए विशेषण देना उनकी राजनीति का हिस्सा बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ऐसे बयानों के जरिए सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्त्रष्टष्ट के शताज़्दी समारोह में पीएम मोदी के भाषण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्त्रष्टष्ट का कार्यक्रम देश के युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य पर चर्चा करने का मौका था, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण एक बार फिर राजनीतिक

अभियान में बदल गया। खरगे ने आरोप लगाया कि युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधने के लिए नए राजनीतिक विशेषणों का इस्तेमाल किया।मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री की कथित %मोडस ऑपरेंडी% पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र में सवालों को दबाने और विपक्ष के लिए नए-नए नाम गढ़ने की राजनीति करती है। इस दौरान खरगे ने नाराज फूफा, दिमागी नज़्सल, अर्बन नज़्सल, खान मार्केट गैंग, आंदोलनजीवी और परजीवी जैसे शज़्दों का जिक्र किया।

खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और कथित जनविरोधी मुद्दों में बदलाव नहीं आया है, लेकिन विपक्ष के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शज़्द हर साल बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सामने बेरोजगारी, लंबे समय से अटकी सरकारी भर्तियां, पेपर लीक, महंगी होती शिक्षा, छात्रवृज़्ति के घटते अवसर और विश्वविद्यालयों की स्वायज़्तता जैसे कई सवाल हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए अपना %रिपोर्ट कार्ड% दिखाया है, लेकिन देश के युवा भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर खड़े हैं। खरगे ने सवाल उठाया कि युवाओं के इन मुद्दों और सवालों पर सरकार की ओर से ज़्या जवाब दिया जा रहा है। इस बयान के बाद पीएम मोदी के स्त्रष्टष्ट भाषण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ऐसे बयानों के जरिए सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्त्रष्टष्ट के शताज़्दी समारोह में पीएम मोदी के भाषण को लेकर सवाल उठाए।

बिहार बाढ़: पटना में गंगा नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पार, १२ जिलों में २२ लाख लोग प्रभावित

पटना ०६/०९ (संवाददाता): बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड में भारी बारिश के बाद नदियों में बढ़े जलस्तर से बिहार के 12 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पटना में रविवार को गंगा नदी का जलस्तर बाढ़ के उच्चतम स्तर को पार कर गया, जिसके बाद अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है। मध्य पूर्व रेलवे ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि पटना-गया खंड पर पुनपुन और परसा बाजार स्टेशनों को जोड़ने वाली पुल संज़्या 21 पर जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाने के कारण कुछ रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है या फिर उनका मार्ग बदला गया है।

अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अभी अलग-अलग जिलों में कुल 190 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही है और प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने और आवाजाही में मदद के लिए 1,429 नावों की सेवा ली जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, अलग-अलग जिलों में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 27 और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 10 टीम तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बाद पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 'बाढ़ के उच्चतम स्तर' (एचएफएल) से ऊपर चला गया है। डज़्ल्यूआरडी के मुताबिक, पटना के गांधी घाट पर रविवार सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 50.57 मीटर था, जो 21 अगस्त 2016 को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम जलस्तर 50.52 मीटर से 0.05 मीटर अधिक है। बयान के मुताबिक, ''पटना जिले के पंडारक में सुबह छह बजे गंगा नदी का जलस्तर 43.92 मीटर था, जो 16 अगस्त 2021 को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम जलस्तर 43.73 मीटर से 0.19 मीटर अधिक है।'' अधिकारियों ने बताया कि राज्य में गंडक नदी डुमरियाघाट और हाजीपुर में, कोसी नदी बलतारा और कुरसेला में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, गंगा नदी बज़्सर, हाथीदह, भागलपुर, कहलगांव एवं मुंगेर में, पुनपुन नदी श्रीपालपुर में, घाघरा नदी दरौली में और बागमती नदी बेनीबाद में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह स्थिति राज्य

और पड़ोसी राज्य झारखंड में हुई भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि सितंबर में अब तक राज्य में 69.1 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 55 प्रतिशत अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बाद पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर उच्च बाढ़ स्तर से ऊपर चला गया है, जिससे अगले एक से तीन दिनों में राज्य की राजधानी में हाथीदह और अन्य स्टेशनों पर असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने बताया कि कई नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बज़्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय और अरवल में लगभग 22.42 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।जल संसाधन विभाग (डज़्ल्यूआरडी) की ओर से जारी नवीनतम परामर्श के मुताबिक, हाथीदह में गंगा का जलस्तर अपने पिछले एचएफएल को पार कर सकता है। इसके मद्देनजर बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। परामर्श में कहा गया, ''अधिकारियों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सतर्क रहें और जरूरत के हिसाब से सावधानी बरतते हुए जलस्तर, तटबंधों, संवेदनशील जगहों और निचले इलाकों पर नियमित नजर रखें।''

इसमें कहा गया, ''अभियंताओं से बाढ़ से निपटने से संबंधित संसाधन और मशीनरी तैयार रखने को कहा गया है।प्रभावित इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि वे नदी के पास न जाएं और सतर्क रहें।'' स्थानीय प्रशासन से कहा गया है कि वे नावों के संचालन पर नजर रखें, क्षमता से अधिक लोगों को नावों पर सवार नहीं होने दें और लोगों को हालात के बारे में जानकारी देते रहें। स्थानीय मौसम विज्ञान कार्यालय के अधिकारी ने अगले दो दिनों के दौरान राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।

इस बीच, विपक्ष ने बिहार में आई बाढ़ को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग की है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार का 76 प्रतिशत इलाका बाढ़ से प्रभावित है और 19 जिलों के 20 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एज़्स' पर की गई पोस्ट में कहा, बीस लाख से अधिक लोग इस आपदा में फंसे हुए हैं, पशुपालकों के मवेशी पानी में डूबकर बह गए हैं। सार्वजनिक ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। हजारों करोड़ के जान-माल की क्षति हुई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया, दिवालिया हो चुकी बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने में उदासीन है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, केंद्र सरकार बिहार की विनाशकारी बाढ़ को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करते हुए तत्काल बेहाल बिहार की मदद के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष विज़्तीय सहायता राशि प्रदान करें तथा बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का सहयोग सुनिश्चित करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया कि वह अविलंब बिहार का दौरा कर यथास्थिति का सर्वेक्षण कर तत्काल राहत पहुंचाएं।

विविध समाचार

सागर में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत

सागर (मध्यप्रदेश)०६/०९ (संवाददाता): सागर जिले की बंडा तहसील में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य की हालत गंभीर है। मामले की शुरुआती जांच में उज़र प्रदेश के ललितपुर से शराब की तस्करी की बात सामने आई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सागर की जिलाधिकारी प्रतिभा पाल ने बंडा में संवाददाताओं से कहा, ''आज तड़के चार बजे यह मामला संज्ञान में आया। इसमें अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

हमारा विशेष ध्यान इस बात पर है कि यदि अन्य लोग भी इसकी चपेट में आए हैं, तो उनकी जांच कराकर उनका उपचार किया जाए।'' मुज़्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच का आदेश देते हुए कहा कि सरकार इसमें सज़्त कार्रवाई करेगी। वहीं, कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है। जिलाधिकारी पाल ने यह भी कहा कि मामले की शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि उज़र प्रदेश के ललितपुर से जहरीली शराब यहां लाई गई। उन्होंने कहा, ''ललितपुर का एक गिरोह इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है। चूंकि यह क्षेत्र उज़र प्रदेश से सटा हुआ है, इसलिए शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है।'' सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने संवाददाताओं से कहा कि जानकारी सामने आते ही जांच शुरू कर दी गई और अब तक जितने भी संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, ''अभी तक जांच में सामने आया है कि जहरीली शराब का स्रोत उज़र प्रदेश का ललितपुर हो सकता है। पहले भी इस प्रकार के मामलों में ललितपुर के गिरोहों की संलिप्तता सामने आई है। इसी दिशा में हम जांच कर रहे हैं।

हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ हो रही है ताकि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़कर मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके।'

' स्थानीय स्तर पर शराब तस्करों को संरक्षण दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर सुजानिया ने कहा कि यदि जांच में इसकी पुष्टि हो जाती है तो उनके खिलाफ भी सज़्त कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सागर की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 110 से 120 किलोमीटर है। इससे पहले, मध्यप्रदेश के उपमुज़्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में 'पीटीआई-वीडियो' से बातचीत में नौ लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ लोगों का अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आबकारी आयुक्त सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी बंडा में मौजूद हैं और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के दौरे पर गए मुज़्यमंत्री यादव ने एक बयान में कहा, ''सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में शराब के सेवन से हुई मौतों का समाचार अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रभारी मंत्री और अधिकारियों को तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में किसी भी दोषी को बज़्शा नहीं जाएगा।'' सागर जिला मुज़्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बंडा क्षेत्र में हुई मौतों को लेकर कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की। पटवारी ने ग्वालियर में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में ''शराब माफिया बेखौफ होकर लोगों की जान ले रहे हैं।'' मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने दावा किया कि सागर में जहरीली-अवैध शराब ने 11 लोगों की जान ले ली है तथा 25 से अधिक लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।

सिंघार ने एक बयान में कहा, ''यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि सरकार की नाक के नीचे चल रहे अवैध शराब के कारोबार और प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर सवाल है।'' उन्होंने कहा कि इससे पहले उज्जैन से नकली शराब का मामला सामने आ चुका है। उन्होंने सवाल किया, ''आखिर मध्यप्रदेश में अवैध शराब का कारोबार कब रुकेगा? किसके संरक्षण में यह जहरीला कारोबार फल-फूल रहा है?'' बंडा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र लोधी ने 11 लोगों की मौत और 25 लोगों के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन होने का दावा किया।

पूर्व विधायक तरवर लोधी ने इस घटना पर कहा कि बंडा विकासखंड के बराज, घूघर, नौराज और आसपास के गांवों में रहने वाले कई लोगों ने शनिवार रात शराब का सेवन किया था, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने बताया कि परिजन उन्हें इलाज के लिए बंडा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने कई लोगों को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि चार-पांच लोग बंडा सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि चार-पांच लोगों को सागर भेजा गया है।

मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 15 फीट गहरा कुआं, कलेज़्ट्रेट परिसर में मचा हड़कंप

नयी दिल्ली ०६/०९ (संवाददाता): कलेज़्ट्रेट परिसर में मस्जिद गिराए जाने के करीब 24 घंटे बाद रविवार को मलबा हटाने के दौरान एक कुआं मिला है। मलबा साफ कर रही टीम को यह कुआं मस्जिद के नीचे मिला। बताया जा रहा है कि कुएं की गहराई करीब 15 फीट और चौड़ाई करीब डेढ़ मीटर है। कुएं के ऊपर एक भारी स्लैब डाला गया था। जब पोकलेन मशीन से स्लैब नहीं टूटा तो टीम ने कटर की मदद से उसे हटाया। स्लैब हटाते ही नीचे कुआं दिखाई दिया। फिलहाल यह साफ नहीं है कि कुआं कब बनाया गया था और यह कितना पुराना है।

कलेज़्ट्रेट परिसर में सरकारी जमीन पर बनी दो मंजिला मस्जिद को शनिवार सुबह प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से गिराया गया था। यह कार्रवाई जिला जज न्यायालय के 2 सितंबर के आदेश के बाद की गई। कार्रवाई के लिए सुबह-सुबह सात बुलडोजर लगाए गए थे। इससे पहले सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई को अपने आदेश में मस्जिद के निर्माण को अवैध माना था।मस्जिद पक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला जज ने 2 सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी थी।

इस मामले की शुरुआत बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत से हुई थी। उन्होंने जनवरी 2025 में मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर आरोप लगाया था कि कलेज़्ट्रेट परिसर में सरकारी जमीन पर कज़्जा करके मस्जिद बनाई गई है। शिकायत की जांच के बाद 24 मार्च 2025 को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई उज़र प्रदेश लोक परिसर (अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के तहत की गई थी। सुनवाई के बाद 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार की 315 वर्ग मीटर जमीन पर कज़्जा करके मस्जिद का निर्माण किया गया है। अदालत ने संबंधित पुराने राजस्व रिकॉर्ड का भी हवाला दिया। रिकॉर्ड में फसली वर्ष 1324 और 1359 में इस जमीन को कचहरी-कलेज़्ट्रेट के रूप में दर्ज पाया गया था। इसके बाद मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए जमीन खाली कराने और कज़्जाधारी से करीब 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया गया था।

मस्जिद पक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ 20 जुलाई को जिला जज कोर्ट में अपील की थी। करीब डेढ़ महीने तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने 2 सितंबर को अपील खारिज कर दी और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार रात ही कलेज़्ट्रेट परिसर की घेराबंदी कर दी थी और बड़ी संज़्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मस्जिद के मलबे के नीचे मिला कुआं इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कुआं कितना पुराना है, इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से होता था और इसे कब बनाया गया था। आगे की जांच के बाद ही इसकी स्थिति और इतिहास के बारे में अधिक जानकारी सामने आ सकेगी।

राहुल गांधी २०२९ में इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, केसी वेणुगोपाल का दावा

त्रिशूर (केरल) ०६/०९ (संवाददाता): कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का नेतृत्व करेंगे। वेणुगोपाल ने उन खबरों का खंडन किया कि तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने अपने नेता और तमिलनाडु के मुज़्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उज़्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया है। वेणुगोपाल पत्रकारों के उन सवालों का जवाब दे रहे थे, जिनमें अगले लोकसभा चुनावों के लिए विजय को प्रधानमंत्री पद के तौर पर पेश किए जाने की बात कही गई।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि टीवीके ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। उन्होंने कहा, ''किसी को भी इस तरह का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी 'इंडिया' गठबंधन का चेहरा होंगे।'' उन्होंने कहा कि छात्रों, किसानों और युवाओं

से जुड़े मुद्दों को लेकर राहुल गांधी की राजनीतिक मुहिम को देशभर में व्यापक स्तर पर समर्थन मिला है।

वेणुगोपाल ने कहा, ''आज भारत में जिस लड़ाई की अगुवाई वह कर रहे हैं, उसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है—चाहे वह छात्रों, किसानों या युवाओं के लिए हो। सभी ने इसे स्वीकार किया है।'' ज़्या गांधी 2029 के चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, इस सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा, ''निश्चित रूप से। राहुल गांधी आज भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। भौगोलिकसंदर्भ

हर कोई राहुल गांधी के फैसलों और उनके कार्यों को बहुत ध्यान से देख रहा है।'' उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में गठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद होने के बावजूद 'इंडिया' गठबंधन मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा, ''इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। कुछ राज्यों में ऐसे मुद्दे हैं, जहां वे एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

लेकिन 'इंडिया' गठबंधन आगे बढ़ रहा है। यही सच्चाई है।'' इंडिया गठबंधन के घटक माकपा का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि केरलम में पार्टी अपनी पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ले रही है। उन्होंने कहा, ''माकपा अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीख रही।

अगर वह सबक सीखने का फैसला भी करती है, तो विपक्ष के नेता पिनराई विजयन उसे ऐसा करने नहीं दे रहे।'' वेणुगोपाल ने कहा कि गठबंधन के भीतर के मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार देश को 'अंधकार युग' की ओर ले जा रही है। नयी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब भी उस कार्रवाई को जायज ठहराने में जुटी हुई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''यह घटना जंतर-मंतर पर हुई थी। केंद्र सरकार अब भी इसे सही ठहराने में लगी हुई है। वह छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी उचित बता रही है।'' वेणुगोपाल ने उज़राखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण वाले मंच के 'शुद्धीकरण' का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि देश अंधकारमय दौर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ''यह भारत को अंधकार युग की ओर ले जा रहा है। देश में इसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई जरूरी है और यही हमारा हित भी है।

भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया युद्धविराम का स्वागत किया

नयी दिल्ली ०६/०९ (संवाददाता): भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया युद्धविराम का स्वागत किया है और उज़्मीद जताई है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2026 को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम युद्धविराम का

स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हम पहले भी लगातार कहते रहे हैं, मौजूदा संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति आवश्यक हैं।

विदेश मंत्रालय ने महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा गलियारे, होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध और सुरक्षित समुद्री यातायात सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया और समुद्री मार्गों में सामान्य स्थिति बहाल होने की आशा व्यक्त की। बयान में कहा गया कि हम हुए युद्धविराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हमने पहले भी लगातार कहा है, मौजूदा संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति आवश्यक हैं। बयान में आगे कहा गया कि इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हमें उज़्मीद है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार का प्रवाह बहाल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य कार्रवाई को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की और कहा कि हमले दो सप्ताह के लिए टाल दिए जाएंगे। यह निर्णय पूर्व निर्धारित समय सीमा से ठीक पहले उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %ट्रुथ सोशल% पर साझा किया गया, जिससे बढ़ते तनाव की तत्काल आशंकाएं कम हो गईं।

ट्रंप ने इस कदम को दोतरफा युद्धविराम बताया, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान अमेरिका और ईरान दोनों से शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से बचने की उज़्मीद है। इस विराम को कूटनीति के लिए जगह बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

राष्ट्रपति के अनुसार, यह निर्णय ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की सहमति के बाद लिया गया है, जो वैश्विक तेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह जलमार्ग अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

जंतर मंतर हमले के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज से दिल्ली पुलिस से पूछे १०० से अधिक सवाल

नयी दिल्ली ०६/०९ (संवाददाता): दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के मामले में गिरज़्तार स्वयंभू हिंदूवादी 'इन्ज़्लुएंसर' स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत के दौरान उसके वायरल वीडियो दिखाकर कई पुलिस टीम ने पूछताछ की। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि 22 वर्षीय भारद्वाज से हिरासत के दौरान 100 से अधिक सवाल पूछे गए।

सूत्र ने बताया कि उसने कुछ सवालों के जवाब दिए, जबकि कई अन्य सवालों का जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने पूछताछ के दौरान भारद्वाज के कई वायरल वीडियो उसे दिखाए और वीडियो में उसके द्वारा दिए गए बयानों तथा किए गए दावों को लेकर उससे सवाल-जवाब किए। सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के दौरान भारद्वाज में अपने कृत्य को लेकर कोई पछतावा नहीं दिखा।

भारद्वाज को शुक्रवार को उज़र प्रदेश के बुलंदशहर में हिरासत में लिए जाने के बाद गिरज़्तार किया गया था। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर के आवास पर अपराह्न करीब दो बजे पेश किया गया, जबकि कानूनी सहायता के लिए नियुक्त वकील वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायाधीश के समक्ष पेश हुआ।

भौगोलिकसंदर्भयह घटनाक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा कथित हमले के संबंध में दर्ज

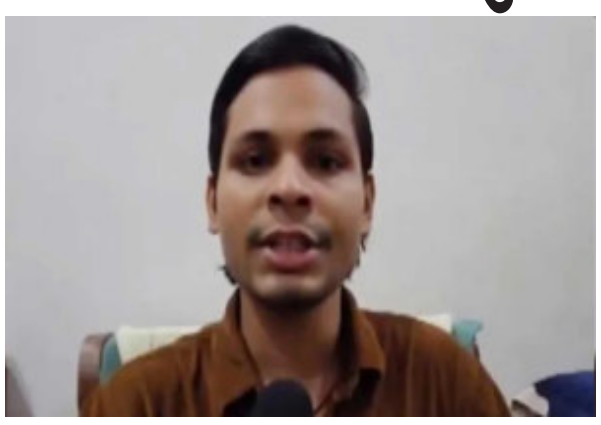

प्राथमिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं और आपराधिक धमकी का आरोप जोड़े जाने के एक दिन बाद हुआ।

नाबालिग छात्र कार्यकर्ता की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉज़्सो) अधिनियम के तहत एक अलग प्राथमिकी भी दर्ज की गई। छात्रा ने आरोप लगाया कि अपने पिता पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाने के बाद उसे ऑनलाइन धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

पुलिस की कार्रवाई एक वीडियो पॉडकास्ट को लेकर हुए आक्रोश के बाद हुई, जिसमें भारद्वाज ने कथित तौर पर दावा किया था कि प्रदर्शन के दौरान उसने नाबालिग छात्र कार्यकर्ता के पिता की ''खोपड़ी फोड़ दी'' थी। बाद में उसने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले कहा था कि छात्र कार्यकर्ता के पिता को लगी चोटें ''साधारण प्रकृति'' की थीं।

अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता मामले की जांच के तहत भारद्वाज के सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री की भी पड़ताल कर रहे हैं। स्वयंभू हिंदुत्व 'इन्ज़्लुएंसर' के कई समर्थक शनिवार को संसद मार्ग थाने के बाहर एकत्र हुए और भारद्वाज के खिलाफ मामला वापस लेने तथा निष्पक्ष जांच की मांग की।

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) का एक प्रतिनिधिमंडल, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ, शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों से मिला और भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने प्राथमिकी में हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी के आरोप तथा एससी/एसटी अधिनियम की धाराएं जोड़ने की मांग की।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक अलग घटनाक्रम में उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने छात्र कार्यकर्ता के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि इसमें आरोप लगाया गया है कि छात्रा ने सोशल मीडिया पर आपज़िजनक पोस्ट के जरिए हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया।

विविध समाचार

रिश्ता चाहे कोई भी हो खास होता है

खुशियों का अहसास अपनो से ही होता है। इसे हमेशा के लिए गहरा करने के लिए कुछ खास बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आने वाला हर पल हसीन रहे। अगर किसी कारण रिश्तों में गलतफहमियां आ भी जाए तो एक दूसरे पर यकीन इतना गहरा हो कि कोई दूसरा आपमें अपनी जगह बना न सके। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है ताकि प्यार से संजो कर रखा गया यह रिश्ता जिंदगी की जरूरत बन जाए।

दुनिया में रिश्ते के बिना प्यार का अहसास ही नहीं हो सकता। इसे निभाने के लिए शुरुआत भी अलग तरीके की होना चाहिए। फिर चाहे वो दोस्ती हो या फिर रिश्तेदारी।

एक दूसरे को जानना जरूरी

आप किसी से प्यार करते हैं तो इसके लिए एक बात को जान लेना बहुत जरूरी है आपको उसकी आदतों के बारे में जानना होगा। इससे आप खुद को और अपने बढ़ते रिलेशनशिप को कुछ समय दे पाएंगे। जो भविष्य में आपके लिए परेशानी नहीं बनेगा।

रिलेशनशिप से बनें पहचान

दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्ती इस तरह की हो जो आपकी पहचान बनें। इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोस्ती में खोते जा रहे हैं। यह बदलाव आपके लिए खतरनाक हो सकता है।

कभी शक भी जायज

जहां यकीन है वहां शक होना भी कभी कभी जायज होता है। पार्टनर पर जरूरत से भी ज्यादा यकीन कर लेने से भी कई बार रिश्ता खराब होने का डर रहता है। थोड़ा बहुत शक करना या फिर पजेसिव होने से पार्टनर को भी पता चलता है कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं।

एक-दूसरे को दें वक्त

एक-दूसरे के साथ समय बिता कर उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। कई बार ज्यादा देर तक बनाई गई दूरी भी रिश्ते में खट्टास पैदा कर सकती है। ऐसे में समय की कमी के कारण अगर पार्टनर के साथ नराजगी है तो एक-दूसरे को समय जरूर दें। कहीं न कहीं आपके रिश्ते में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करें एक- दूसरे के साथ समय बिताएं।

कुछ इस तरह सेट करें मंथली बजट

हर व्यक्ति अपनी पसंद व स्किल्स के अनुसार ही काम का चयन करता है और इसलिए हर किसी का काम व इनकम अलग होती है। जहां कुछ लोग 9 से 5 की जॉब करते हैं और उनकी फिक्स सैलरी होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किसी जॉब में नहीं होती। बल्कि उनका काम कुछ ऐसा होता है कि उनकी इनकम ऊपर-नीचे होती रहती है। मसलन, अगर आपका अपना कोई काम है, तो आप महीने में होने वाली आमदनी को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसी तरह, अगर आप बतौर फ्रीलांसर फुल टाइम वर्क करते हैं, तो आपकी आमदनी आपको मिलने वाले प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करेगी।

इस तरह के कामों में आमदनी कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत ही कम होती है। इस तरह सैलरी फिक्स ना होने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आपके लिए घर का खर्च उठाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। चूंकि, आपकी आमदनी फिक्स नहीं है तो उसके अनुसार आप अपनी सैलरी को सही तरह से मैनेज नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसा है, तो ऐसे में आप अपना मंथली बजट सेट करने के लिए इन आसान टिप्स की मदद लें

अनुमानित आय का करे आकलन

यह सच है कि आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को मिलने वाले काम के अनुसार अपनी आय का एक अनुमान तो लगा ही सकती हैं। अगर आपकी आय ऊपर-नीचे होती भी होगी, तो उसमें पांच-दस हजार का अंतर आता होगा। इसलिए, आप पिछले एक वर्ष की आय का अंदाजा लगाते हुए यह जानने का प्रयास करें कि आपकी महीने में लगभग कितनी इनकम होती है। जब आप अपनी आय का आकलन करेंगी, तभी आप बजट सेट कर सकती हैं।

जरूरी खर्चों की बनाएं लिस्ट

अब वक्त है जरूरी खर्चों की लिस्ट तैयार करने का। मसलन, बच्चों की फीस से लेकर ईएमआई, घर का किराया व बिजली बिल आदि जरूरी खर्चों की एक लिस्ट तैयार करें। इससे आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि वास्तव में कितने खर्च ऐसे हैं, जो आपको हर महीने करने ही होंगे और उसके अनुसार आपकी इनकम कितनी है।

निकालें सेविंग्स का एक हिस्सा

जब आप जरूरी खर्चों व इनकम के बीच के अंतर के बारे में जान जाते हैं, तो आपको बची हुई इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स के लिए निकालना होगा। आपके द्वारा की गई सेविंग्स आपकी इनकम के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप सेविंग की आदत को कभी भी ना छोड़ें।

चूंकि आपकी इनकम कभी भी एक जैसी नहीं रहती है और इसलिए आपके लिए सेविंग्स करना बेहद आवश्यक हो जाता है।

बनाएं इमरजेंसी मनी बैंक

यह इमरजेंसी मनी बैंक उस वक्त के लिए बनाना आपके लिए आवश्यक है, जब आपकी इनकम बहुत कम हो जाती है और आपके लिए अपनी आय से जरूरी खर्चों को कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। उस वक्त यह इमरजेंसी मनी बैंक काम आता है। अगर इस वक्त आपका काम अच्छा चल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बेफिजूल खर्चों में पैसों को बर्बाद कर दें। आपको अपना मंथली बजट यू सेट करना चाहिए कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा एंटरटेनमेंट के लिए तो एक हिस्सा इमरजेंसी मनी बैंक के लिए रखें। यह छोटा सा मनी बैंक आप खुद घर में ही बना सकते हैं या फिर ऐसे किसी स्कीम में इनवेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके पैसे धीरे-धीरे कुछ हद तक बढ़ते रहे और जब भी आपको उसकी जरूरत हो, आप उसे निकाल सकें।

ऐप की लें मदद

यह मंथली बजट बनाने का सबसे आसान लेकिन प्रभावी तरीका है। आजकल ऐसे कई ऐप हैं, जिन्हें आप अपने फोन में इस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद, आप उसमें हर माह की आय लिख सकती हैं और मंथली बजट लिमिट एड कर सकती हैं। उसके बाद आप हर दिन होने वाले खर्चों को उसमें एड करती जाएं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आप सबसे अधिक खर्चा कहां कर रही हैं और क्या आप अपने मंथली बजट के अनुसार खर्चे कर रही हैं। इस तरह आपके लिए बजट में रहना आसान होगा और अपनी आय व खर्चों को ट्रैक करने में भी आपको मदद मिलेगी।

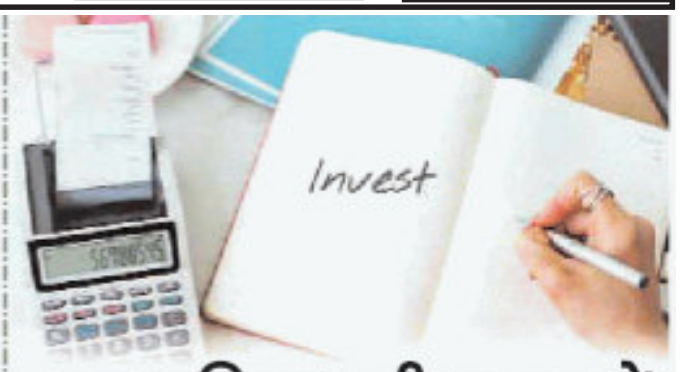

घर-परिवार की जरूरतों और भविष्य को देखते हुए बचत बहुत जरूरी

महिलाएं चाहती हैं कि घर परिवार में संपन्नता रहे, परिवार के सदस्यों को रुपये-पैसे की कमी ना आए, इसके लिए महिलाएं अपनी खर्चों में भी काफी कटौती करती हैं। इसके बावजूद अक्सर ऐसा होता है कि महीने के आखिर तक आते-आते पैसे खत्म हो जाते हैं और सेविंग्स भी नहीं हो पातीं। घर-परिवार की इमरजेंसी की जरूरतों और भविष्य को देखते हुए महिलाओं के लिए बचत करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्च बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से आपको सेविंग्स नहीं हो पातीं, तो आपको नए नजरिए से सोचने की जरूरत है। आपकी आमदनी चाहे भले ही कम क्यों ना हो, अगर आप घर का बजट सही तरीके से बनाएं, तो आप थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करके भी बड़ी बचत कर सकती हैं। आइए जानते हैं महीने का बजट बनाने के कुछ ऐसे तरीके, जिनसे आपका घर का फाइनेंस अच्छे तरीके से मैनेज होगा, जरूरी खर्चों के लिए पैसे रहेंगे और आप सेविंग्स करने में भी कामयाब होंगी।

- बजट बनाने में सबसे पहले अपने बड़े और जरूरी खर्चों की लिस्ट बना लें, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का राशन, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बकाया आदि।
- बजट बनाने में खाने-पीने की चीजों पर कटौती नहीं करें। अगर आप अनाज जैसे कि दाल, गेहू, चावल, मसाले आदि थोक की दुकान से खरीदेंगी तो पैसे की बचत के साथ-साथ अच्छी क्वालिटी का सामान भी खरीद सकती हैं। मुमकिन हो तो सुपर मार्केट के बजाय लोकल मार्केट से ही अच्छा सामान खोजने की कोशिश करें। साथ ही मॉल में छोड़े-बड़े सामान पर मिलने वाले ऑफर और सेल का भी आप फायदा उठा सकती हैं।
- घर का बजट बनाते हुए उसमें अपने, अपने परिवार के बड़ों और बच्चों के खर्च जरूर शामिल करें। आप चाहें तो उनसे इस बारे में एक बार बात भी करें और उसी के आधार पर सबके लिए बजट निर्धारित कर लें।
- बिजली और गैस का यूज जरूरत के हिसाब से करें। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी-छोटी बचत भी आपके लिए अच्छी सेविंग्स का साधन बन सकती है, बजट को और मजबूत बना सकती है।
- बजट बनाते समय अपनी इनकम और खर्च का रिकार्ड साथ में रखें, क्योंकि इसी के आधार पर आप सेविंग्स के लिए अपना टार्गेट सेट कर सकती हैं और एक अच्छा बजट बना सकती हैं। इसके लिये एक निर्धारित फॉर्मेट बना लें और उस पर अपनी इनकम और होने वाले खर्चों को उसमें जोड़ते जाएं।
- अपनी पसंद वाली छोटी और बड़ी चीजों की एक लिस्ट अलग से बनायें, जिन चीजो की जरूरत ज्यादा है, उन्हें प्रायोरिटी पर रखे। कभी-कभी मजे-मजे में अनावश्यक फिजूलखर्ची भी हो जाती है और इससे बाद में परेशानी होती है। इसे देखते हुए जब भी पार्टी करने जाएं या आउटिंग पर जाएं तो उसके लिए अपने खर्च की लिमिट पहले से ही सोच लें।
- बजट को बोझ समझकर मन छोटा ना करें। शुरूआत में आपको इससे प्रेशर फील हो सकती है, लेकिन इससे होने वाली बचत से आपको बाद में बड़े फायदे हो सकते हैं।
- बजट बनाने से आप अपने खर्चों पर असरदार तरीके से काबू रख सकती हैं और फाइनेंशियली मजबूत हो सकती हैं।
- बजट बनाते हुए अलग-अलग खर्चों के लिए अलग लिफाफे रखें, ताकि फाइनेंस के मामले में आप पूरी तरह से ऑर्गनाइज रहें। इससे आपको महीनेभर खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इमरजेंसी की जरूरतों के लिए एक लिफाफा अलग से बनाएं और इसमें भी कुछ रुपये अलग से रखें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है और इससे आपका महीने का बजट पूरी तरह से बिगड़ सकती है।

शादी के बाद आ रही है मायके की याद तो अपनाएं ये उपाय

शादी के बाद लड़की की जिन्दगी काफी हद तक बदल जाती है। वह अपने पति के साथ सात फेरे लेने के बाद उन्हीं के घर में रहने लग जाती है। यह एक ऐसा दौर होता है, जब एक स्त्री को नए रिश्तों और नए परिवार के साथ तालमेल बिठाना होता है। हालांकि, पूरी तरह से नए व अनजान लोगों के बीच अक्सर लड़की को अपने माता-पिता, भाई-बहन व घर की याद सताती है। शादी के शुरूआती दिनों में अक्सर लड़कियां होम सिक फील करती हैं और ऐसे में वह बार-बार अपने मायके जाने की इच्छा रखती हैं। हालांकि, हर दिन ऐसा करना संभव नहीं है। तो ऐसे में अब आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने की जरूरत है, जिसके कारण आपको अपने मायके की याद कम से कम आए और आपके लिए अपने नए घर में मन लगाना अधिक आसान हो जाए।

वीडियो कॉल पर करें बात

हो सकता है कि शादी के शुरूआती दिनों में आपका बार-बार मायके जाना शायद आपके ससुराल पक्ष के लोगों को पसंद ना आए। चूंकि, अब आपको हर किसी की खुशी का ख्याल रखना होता है, तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीडियो कॉल पर अपनी फैमिली से बात करें। जब आप उनसे वीडियो कॉल पर बात करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वह आपके साथ ही हैं। इससे आपके लिए उनकी याद कम सताएगी।

मंगवाए फेवरिट फूड

हम सभी को अपनी मम्मी के हाथों का बना कोई ना कोई फूड आइटम खाना बेहद पसंद होता है। मसलन, मां के हाथ के लड्डू या नमकपारों का स्वाद अगर आपको हमेशा से ही अच्छा लगता है, तो आप मम्मी से कह सकती हैं कि वह आपके लिए इसे बनाकर भेजें। जब वह आपकी फेवरिट आइटम आपको भिजवाएंगी तो आप ससुराल में होते हुए भी उनकी या उनके खाने को मिस नहीं करेंगी। इस तरह आप उनसे दूर होते हुए भी उनके साथ को महसूस कर पाएंगी।

ना रहें अकेली

यह देखने में आता है कि शादी के बाद शुरूआती दिनों में विवाहित स्त्री अपना अधिकतर समय अपने कमरे में ही बिताती है। चूंकि इस समय पर उस पर घर की बहुत अधिक जिम्मेदारियां नहीं होती हैं और वहीं वह नए लोगों के साथ बहुत अधिक कंफर्टेबल नहीं होती है, इसलिए वह कमरे में रहना ही अधिक पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं, तो इससे आपको अपने मायके की याद और भी अधिक सताएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप कमरे में अकेले रहने के स्थान पर अपने ससुराल पक्ष के लोग जैसे सास या ननद के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताने की कोशिश करें जब आप ऐसा करती हैं, तो आपको नए लोगों के साथ तालमेल बिठाने में आसानी होती है और उनके साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। जब ऐसा होता है, तो आपको मायके की याद कम सताती है।

मिल आएं कुछ देर

अगर आपका मायका पास में ही है और आपके लिए एक-दो घंटे के लिए वहां जाना संभव है, तो ऐसे में आप अपने पति के साथ मायके में कुछ देर के लिए जा सकती है। अपनों से मिलने की खुशी कुछ और ही होती है। भले ही आप उनसे एक घंटे के लिए मिलने जाएंगी, लेकिन परिवार के हर सदस्य को देखकर और उनके साथ वक्त बिताकर आपको काफी अच्छा लगेगा।

कलिंग समाचार

संपादकीय

संघ के सौ साल पर प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति

इस साल 15 अगस्त को लालकिले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खुल कर सराहना की थी। श्री मोदी ने संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बताया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खुद को सांस्कृतिक संगठन ही बताता है, जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन यह खुला तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी संघ के कारण ही अस्तित्व में आई और आज सत्ता पर विराजमान है। इस तथ्य को पहले श्री मोदी के बयान से बल मिला और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह का आयोजन किया। विजयादशमी पर संघ की स्थापना के सौ साल पूरे होने से पहले 1 अक्टूबर को दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। 1 तारीख के अखबारों में संस्कृति मंत्रालय ने संघ के शताब्दी समारोह के बड़े-बड़े विज्ञापन जारी किए। मंत्रालय ने इन विज्ञापनों के लिए लाखों रूपए जनता की गाढ़ी कमाई से हासिल टैक्स से दिए होंगे। यहां सवाल बनता है कि किसी गैर सरकारी संगठन के लिए सरकार क्यों विज्ञापन दे रही है, उसके शताब्दी समारोह का आयोजन सरकार क्यों कर रही है और किस अधिकार से जनता के धन को एक गैर सरकारी संगठन के प्रचार पर खर्च किया जा रहा है। हालांकि ये सिलसिला केवल कार्यक्रम आयोजन और विज्ञापन तक ही सीमित नहीं रहा। बुधवार 1 अक्बूटर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में नए 100 रुपये के सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए, जिस पर भारत माता की तस्वीर छपी हुई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ के सौ साल महज संयोग नहीं है, ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था जिसमें राष्ट्र चेतना, समय-समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए-नए अवतारों में प्रकट होती है। इन शब्दों का विश्लेषण करें तो इसमें वही ध्वनि सुनाई देगी, जिसमें नरेन्द्र मोदी खुद को नॉनबायलॉजिकल बताते हैं। भगवत गीता में लिखा है- यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अयुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजा यहम् ॥ 4.7॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता । धर्मसंस्थापनार्थाय स भवामि युगे युगे॥ 4.8 ॥ अर्थात जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं प्रकट होता हूं (अवतरित होता हूं)। साधुजनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। अब सवाल ये है कि क्या नरेन्द्र मोदी ने खुद को अवतरित बताने के साथ-साथ संघ के लोगों को भी अवतारी बताने की कोशिश की है। क्या श्री मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, तब राष्ट्र चेतना जगाने और उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए अवतार की जरूरत थी। अगर श्री मोदी की बात का यही अर्थ है, तब एक नया सवाल उठता है कि 1930 में जब गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरु किया, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरु हुआ, तब संघ के किसी भी सदस्य ने उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं की। क्या इन आंदोलनों से राष्ट्रचेतना जाग्रत नहीं हो रही थी, या फिर संघ उस युग की असली चुनौती गुलामी को नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना को मानता था। यह स्थापित तथ्य है कि संघ के लोगों ने किसी भी तरह आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी नहीं की। वी डी सावरकर भी अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से निकल गए थे, इसके प्रमाण मौजूद हैं। संघ के लोग महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहे, यह भी इतिहास में दर्ज है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने अपनी पत्रिका अग्रणी के 1945 के अंक में एक कैरिकेचर प्रकाशित किया था, जिसमें रावण के सिर की जगह महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी जैसे नेताओं के सिर दिखाए गए थे, और उन पर बाण चलाने वाले के रूप में वी डी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दर्शाया गया था।

क्या नक्सलवाद का यह समाधान आधा-अधूरा है

अरविन्द मोहन

देश के अंदर किसी भी व्यक्ति या संगठन की ताकत शासन और व्यवस्था को चुनौती देने वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी इलाके में वीरप्पन का तो कहीं किसी नक्सल समूह या संविधान में आस्था न रखने वाले अलगाववादी समूह का %राज% चलता रहा है तो वह या तो शासन की कमजोरी थी या उसकी तरफ से ढील का उदाहरण। कई बार लोकतान्त्रिक शासन में इस तरह के ढील की भी जरूरत होती है और समय तथा अवसर देखकर उस नाराजगी को संभाल लिया जाता है। लेकिन साठ के दशक के अंत से क युनिष्ट आंदोलन का एक समूह हथियारबंद क्रांति करके सत्ता छीनने और क युनिष्ट राज कायम करने के सपने के साथ निरंतर सक्रिय है।

आम तौर पर आलोचना का शिकार बनने वाला गृह मंत्रालय अगर नक्सल समस्या को निपटाने की अपनी ताजा मुहिम के चलते तारीफ पा रहा है तो वह और उसके निर्देश पर काम करने वाली सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अभी गृह मंत्रालय द्वारा तय डेडलाइन आने में पाँच-छह महीने का वक्त है और नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में उल्लेखनीय कमी आ गई है। नक्सल प्रभावित जिलों की सं या 18 से घटकर 11 होना इस कमी को ढंग से नहीं बताता क्योंकि अब उन 11 जिलों में भी उनका दम काफी कम रहा गया है और उनका कैडर मैदान छोड़ने की ऊहापोह वाली अवस्था में है या मारा गया है।

सरकार ने स ती के बाद सरेंडर का सही विकल्प रखा तो शीर्ष नेतृत्व समेत बड़ी सं या में हथियारबंद कैडर ने आत्मसमर्पण किया। यह अनुमान है कि हाल में मारे गए या समर्पण वाले नेताओं के अलग होने के बाद भाकपा (माओवादी) के पॉलित ब्यूरो के सिर्फ तीन ही सदस्य बच गए हैं जिनमें एक उम्र और बीमारी के चलते निष्क्रिय हैं। केन्द्रीय समिति के भी आठ या नौ सदस्य ही सक्रिय हैं। कभी पॉलिट ब्यूरो में एक दर्जन से ज्यादा सदस्य थे और सेंट्रल कमेटी में 40 से 45.

देश के अंदर किसी भी व्यक्ति या संगठन की ताकत शासन और व्यवस्था को चुनौती देने वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी इलाके में वीरप्पन का तो कहीं किसी नक्सल समूह या संविधान में आस्था न रखने वाले अलगाववादी समूह का %राज% चलता रहा है तो वह या तो शासन की कमजोरी थी या उसकी तरफ से ढील का उदाहरण। कई बार लोकतान्त्रिक शासन में इस तरह के ढील की भी जरूरत होती है और समय तथा अवसर देखकर उस नाराजगी को संभाल लिया जाता है। लेकिन साठ के दशक के अंत से क युनिष्ट आंदोलन का एक समूह हथियारबंद क्रांति करके सत्ता छीनने और क युनिष्ट राज कायम करने के सपने के साथ निरंतर सक्रिय है। इसमें भी टूट-फुट हुई और बिखराव आया लेकिन नेपाल से लेकर दक्षिण तक के आदिवासी और वन प्रदेशों वाली पट्टी से बने दंडकारण्य (काल्पनिक) वाले इलाके में नक्सली समूह जमे रहे हैं। बिहार, बंगाल, असम, ऑडिसा, छतीसगढ़, आंध्र, महाराष्ट्र के साथ ही पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके इनके प्रभाव में थे। यहां की दरिद्रता और लूट उनके लिए आधार बनाने का काम करते हैं तो गहरे गहने जंगल और फौज-सेना की आवाजाही के लिए मुश्किल भौगोलिक बनावट हथियारबंद दस्तों के छुपने और काम करने का।

देश के अंदर किसी भी व्यक्ति या संगठन की ताकत शासन और व्यवस्था को चुनौती देने वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी इलाके में वीरप्पन का तो कहीं किसी नक्सल समूह या संविधान में आस्था न रखने वाले अलगाववादी समूह का %राज% चलता रहा है तो वह या तो शासन की कमजोरी थी या उसकी तरफ से ढील का उदाहरण। कई बार लोकतान्त्रिक शासन में इस तरह के ढील की भी जरूरत होती है और समय तथा अवसर देखकर उस नाराजगी को संभाल लिया जाता है। लेकिन साठ के दशक के अंत से क युनिष्ट आंदोलन का एक समूह हथियारबंद क्रांति करके सत्ता छीनने और क युनिष्ट राज कायम करने के सपने के साथ निरंतर सक्रिय है।

अब यहां ज्यादा विस्तार से चर्चा का मतलब नहीं है कि हिंसा के सहारे राज्य सत्ता हासिल करने का जो सपना हमारे नक्सली समूह देखते और दिखाते रहे हैं वह एक असंभव ही स्थिति है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं भरे समाज में इस तरह से सत्ता हासिल करना मुश्किल है। इससे भी बड़ी बात यह है की वे जिस विकास और स्वर्ग की कल्पना करते रहे हैं उसका भी रूप दुनिया ने देखा और विदा किया है। समाज और मनुष्य जाति के बुनियादी स्वभाव से भी इस तरह की क्रांति का रास्ता मुश्किल है। और फिर जिस विकास की वे कल्पना करते रहे हैं वह खुद से समानता पर आधारित नहीं है। पार्टी संगठन से लेकर शासन का स्वरूप और कारपोरेट विकास के माडल में एक निश्चित श्रेणीबद्धता है और उसके बगैर काम नहीं चलता। फिर हमारे नक्सली समूहों को गाँव में या जंगल के इलाके में मुश्किल से अपना गुजर करने वाले %जमींदार; और %महाजन% तो वर्ग शत्रु दिखते थे लेकिन शहरी अमीर और कारपोरेट घरानों की पूंजी और ताकत दिखाई नहीं देती थी। बल्कि की जंगली इलाकों में यह भी सुना गया कि बड़े कारपोरेट हाउस वाले अपने वहां के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कंपनियों से नियमित रकम दे करके उनको काम करने देते थे और इस प्रकार उसी पूंजी से समाजवादी क्रांति करने का सपना देखते थे।

और इन सब गलतियों या दिग्भ्रम के बावजूद वे किस तरह बड़ी सं या में लड़के=लड़कियों को अपने रास्ते को अपनाने के लिए राजी करते थे, इतना जोखिम उठाने को प्रेरित करते थे और एक के मरने पर अनेक के खड़ा हो जाने का चमत्कार करते थे यह जानना मुश्किल नहीं है। इसका एक कारण तो देश और समाज में गरीबी और बदहाली के स्थायी ठिकाने बनना है जो इलाका से लेकर सामाजिक समूहों में दिखाता है। जाति के सवाल को ऊपर न करने वाले नक्सली समूहों में ज्यादातर कैडर दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों से आता था क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता और अपमान का जीवन जीते आये हैं।

दूसरा कारण स्थापित दलों और सरकारों का रवैया रहा है जिनके लिए समाज के ऐसे समूह सिर्फ वोट के समय याद आते हैं। सारी नीतियां और कार्यक्रमों का झुकाव शहरों और पैसेवालों की तरफ रहा है। और कई बार न्यस्त स्वार्थ, लोकतंत्र या मानवाधिकार के नाम पर कुछ ढील बरती जाती रही है। इस बार वह नहीं दिख रहा है। इसलिए गिनाने लायक सफलता दिखती है। पर नीतियों और कार्यक्रमों के मामले में कोई फरक आया नहीं दिखाता। जिन पिछड़े इलाकों में नक्सली जमे रहे हैं वहां के विकास के लिए खास कार्यक्रम देने और चलाने की जगह इस पूरे इलाके को बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपने का काम हो रहा है। जिस भूपति के सरेंडर को सरकार या हम सब एक बड़ी घटना मान रहे हैं उन्हें उसे गढ़चिरोली इलाके में जम रही लायड स्टील कंपनी अपना ब्रांड अंबेसडर बना रही है। कंपनी ने हिंसा का मार्ग छोड़ने वाले नक्सलियों को काम देने की घोषणा भी की है। थोड़े से नक्सलियों का इस किस्म का पुनर्वास क्या सारी समस्याएं खत्म कर देगा। इन घोर जंगली इलाकों में बाजार की लूट और कमाई के असीमित स्रोत हैं और सरकार वहां के निवासियों और आदिवासियों के व्यापक पुनर्वास की जगह बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां पहुंचाने में लगी है। यह काम पूर्व की सरकारों ने भी किया है लेकिन आज यह ज्यादा तेजी से होने लगा है। जाहिर तौर पर वहां काम करना है तो इन्ही आदिवासियों और गरीब लोगों से कराना होगा लेकिन सरकार के मौजूदा तरीकों से मालिक कोई और हो जाएगा।

छोटी जोत या वन क्षेत्र की मिल्कियत आदिवासियों को सौंपने के अपने खतरे हैं लेकिन एक लंबे समय तक या खास विकास होने तक जमीन की बिक्री पर रोक जैसी शर्तों के साथ उनको मालिक और मजदूर दोनों बनाने की नीति ही स्थायी समाधान देगी। इसके बगैर आज की सफलता आधी अधूरी ही रहेगी और जरा सी ढील होते ही नए भूपति, नए किशन जी, नए बासवराजू पैदा होने को तैयार ही बैठे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव में भारत कर रहा ऊर्जा पुनर्संतुलन

के रवींद्रन

इस बदलाव के लिए भारत की लाभ संरचना तात्कालिक नहीं है। हालांकि रूसी कच्चे तेल से दूर जाने से भू-राजनीतिक जोखिम कम होता है, लेकिन इससे मास्को द्वारा दी जाने वाली भारी छूट तक पहुंच भी कम हो जाती है- एक ऐसी छूट जिसने भारत को अपने आयात बिल को कम करने और घरेलू उद्योग के मार्जिन को सहारा देने में मदद की थी। लगता है कि वाशिंगटन के बढ़ते दबाव के चलते नई दिल्ली अपनी कच्चे तेल की सोर्सिंग रणनीति में बदलाव कर रही है, जो मास्को से दूर होकर अमेरिका के साथ गहरे संबंधों की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। पिछले कुछ महीनों में, प्रमुख निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी यूराल क्रूड की नई खरीद बंद कर दी है या रोक दी है, और सरकारी अधिकारी सार्वजनिक रूप से रूस से परे आपूर्ति विकल्पों के विस्तार और अधिक अनुकूल अनुबंध शर्तों की ओर इशारा कर रहे हैं। यह बदलाव भारत में अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ मेल खाता है- घरेलू आंकड़े बताते हैं कि इस सप्ताह अमेरिका से आयात की मात्रा लगभग 540,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो 2022 के बाद से दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है।

यह अंतर्निहित गतिशीलता अमेरिकी प्रशासन द्वारा ऊर्जा-व्यापार उत्तोलन को एक भू-राजनीतिक साधन के रूप में मुद्रीकृ त करने के निर्णय से प्रेरित प्रतीत होती है। वाशिंगटन ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया है, जो स्पष्ट रूप से भारत द्वारा रियायती रूसी तेल की बड़े पैमाने पर निरंतर खरीद से जुड़ा है। समानांतर रूप से, वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भारत के रूसी-तेल आयात में सार्थक कमी एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक पूर्व शर्त है। नई दिल्ली के लिए, अब गणित बदल गया है- ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना सर्वोपरि है, फिर भी उच्च टैरिफ को सहन करने और अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के साथ व्यापार संबंधों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम ने यथास्थिति को तेजी से अस्थिर बना दिया है।

रूस के दृष्टिकोण से, यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के कारण लगे प्रतिबंधों के जवाब में कई पश्चिमी खरीदारों के पीछे हटने के बाद, भारत उसकी ऊर्जा पहुंच का एक प्रमुख स्तंभ बन गया था। सितंबर तक छह महीनों में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात लगभग 17.5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय खपत का लगभग 36 प्रतिशत है। इस महीने भारतीय रिफाइनरियों द्वारा अनुबंधों की समीक्षा, विशेष रूप से रोसने ट और लुकोइल जैसे प्रमुख रूसी उत्पादकों से संबंधित अनुबंधों की, जो अब अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं, यह दर्शाती है कि भारत सरकार प्रतिबंध व्यवस्था के साथ तालमेल का संकेत दे रही है, जबकि वह अपनी ऊर्जा-स्वायत्तता विशेषाधिकारों पर ज़ोर दे रही है।

अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में अचानक वृद्धि आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय रिफाइनर मिडलैंड डब्ल्यूटीआई और मार्स जैसे अमेरिकी ग्रेड के कच्चे तेल की बुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने हाल के ह तों में व्यापक ब्रेंट-डब्ल्यूटीआई प्रसार और कमजोर चीनी मांग के कारण एक व्यवहार्य आर्बिट्रेज की पेशकश की है। हालांकि, विश्लेषक आगाह करते हैं कि यह संरचनात्मक पुनर्संरेखण के बजाय एक अस्थायी उपाय है- लंबी समुद्री यात्रा, अमेरिकी ग्रेड से कम उत्पादन और अधिक माल ढुलाई अभी भी इस बदलाव को निकट भविष्य में सीमित कर सकती है। फिर भी, यह तेजी एक मजबूत संदेश देती है- नई दिल्ली अपने सोर्सिंग निर्णयों को भू-राजनीतिक रूप से अधिक लचीला बनाने की क्षमता प्रदर्शित कर रही है।

तेल बाजार की प्रतिक्रियाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि व्यापारी पहले से ही भारत द्वारा बड़े पैमाने पर रूसी तेल खरीद के अंत की आशंका जता रहे हैं। हाल के वर्षों में वैश्विक मूल्य गतिशीलता में एक प्रमुख कारक, यूराल क्रूड द्वारा प्राप्त छूट कम हो गई है, जबकि भारत में व्यापार करने वाले कार्गो बाजारों में जोखिम प्रीमियम बढ़ गया है। वास्तव में, रूस द्वारा छूट वाले बैरल को स्थिर करने वाले के रूप में भारत की पूर्व भूमिका उलट गई है, जिससे वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों के बीच पुनर्संतुलन को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर, भारी छूट वाले रूसी बैरल को छोड़ने से रिफ़ाइनरियों का लागत आधार बढ़ जाएगा, जिससे संभावित रूप से डाउनस्ट्रीम ईंधन और पेट्रोकेमिकल मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ती अस्पष्टता के बीच रिफ़ाइनरों को अनुबंध-रोलओवर के फ़ैसलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कुछ ने प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़ी बुकिंग पहले ही रद्द कर दी हैं, वहीं अन्य बैंकों और बीमा कंपनियों से इस बारे में स्पष्टता का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या प्रतिबंधित उत्पादक आपूर्ति श्रृंखला को द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम को बढ़ाए बिना सेवा प्रदान की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि भले ही भारत के सार्वजनिक बयान अस्पष्ट हैं, और सरकार औपचारिक रूप से किसी भी निर्देश जारी होने से इनकार कर रही है, व्यवहार में उद्योग जगत के खिलाड़ी अपने व्यवहार को अपेक्षित नीतिगत परिणामों के अनुरूप बना रहे हैं। राजनीतिक गणना स्पष्ट है- अमेरिकी मांगों को मानना महंगा है, फिर भी अनुपालन न करने से भारत के विकास मॉडल के लिए बड़े जोखिम हैं, जहां ऊर्जा लागत, व्यापार पहुंच और कूटनीतिक लचीलापन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। रूस के लिए यह घटनाक्रम एक रणनीतिक झटका है, हालांकि घातक नहीं। मास्को अपने रियायती कच्चे तेल के लिए एक प्रमुख स्रोत खो देगा, जिससे उसे या तो चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी या कहीं और ज़्यादा छूट देनी पड़ेगी। हालांकि, चीन की अतिरिक्त बड़ी मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता उसकी अपनी आयात सीमा और वैश्विक व्यापार परिदृश्यों से सीमित है- इसका मतलब है कि आगे चलकर मास्को को आपूर्ति-श्रृंखला पर और अधिक दबाव और मार्जिन पर अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के नज़रिए से, ऊर्जा व्यापार का लीवर कारगर रहा है। भारत को मजबूर कर उसके अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में वृद्धि और रूसी बैरल पर अपनी निर्भरता कम करके, वाशिंगटन उस क्षेत्र में अपनी पहुंच मज़बूत कर रहा है जिसे वह बीजिंग के साथ अपनी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही, अमेरिकी उत्पादकों को एक नया बाज़ार मिलता है, जो %अमेरिका फ़र्स्ट% ऊर्जा-निर्यात एजेंडे के साथ मेल खाता है। नई दिल्ली के लिए, यह बदलाव कठिन और जटिल है- सरकार को सस्ती ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखनी होगी, रिफाइनिंग मार्जिन की व्यवहार्यता बनाए रखनी होगी, और अपनी बहुध्रुवीय कूटनीति की रक्षा करनी होगी - और साथ ही वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह में बदलती शक्ति-खेल के अनुकू ल ढलना होगा। इस बदलाव के लिए भारत की लाभ संरचना तात्कालिक नहीं है। हालांकि रूसी कच्चे तेल से दूर जाने से भू-राजनीतिक जोखिम कम होता है, लेकिन इससे मास्को द्वारा दी जाने वाली भारी छूट तक पहुंच भी कम हो जाती है- एक ऐसी छूट जिसने भारत को अपने आयात बिल को कम करने और घरेलू उद्योग के मार्जिन को सहारा देने में मदद की थी। अमेरिकी ग्रेड की डिलीवरी लागत अधिक होने और मध्य-पूर्वी विकल्पों के भारत की भारी-रूपांतरण रिफाइनरियों के लिए कम अनुकूल उत्पाद प्रोफ़ाइल होने के कारण, मार्जिन में कमी वास्तविक है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन के लिए पाइपलाइन, माल ढुलाई और संविदात्मक अनुकूलन की आवश्यकता होगी- इनमें से कोई भी संक्रमणकालीन व्यवधानों के बिना रातोंरात नहीं हो सकता। जैसे-जैसे भारतीय रिफाइनर रूसी उत्पादकों से नए ऑर्डर कम या बंद कर रहे हैं और अमेरिकी ग्रेड बढ़ा रहे हैं, वैश्विक तेल बाजार एक नए संतुलन के अनुकूल हो रहे हैं। रूसी कच्चे तेल के लिए छूट की खिड़की और भी बंद हो सकती है, जिससे आर्बिट्रेज सेट कम हो सकता है जिसने भारत और अन्य देशों को मास्को-डिस्काउंट खेल से लाभ कमाने में मदद की थी।

विविध समाचार

12 वर्षों में पीएम मोदी ने 17 बार किया हरियाणा का दौरा अपनी 'कर्मभूमि' को दी विकास की बड़ी सौगात : नायब सैनी

चंडीगढ। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के लगातार 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्र लिखकर बधाई दी है। इसके साथ ही हरियाणा को प्रधानमंत्री की कर्मभूमि बताते हुए राज्य को दी गई परियोजनाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र में लिखा, "आपके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा की पौने तीन करोड़ जनता की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह अवसर आपके वंदन का है, अभिनंदन का है। आज आप भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर निर्वाचित व जन–जन के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। हमारी हरिभूमि ने ही आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखने का संकल्प लिया था। आपको याद होगा कि 15 सितंबर, 2013 को रेवाड़ी में आयोजित देश के पूर्व सैनिकों की रैली से आपने अपने 2014 के लोकसभा चुनावों के अभियान की शुरुआत की थी। हमें पूरा विश्वास है कि उस रैली का उत्साह और आपके प्रति प्यार अभी भी आपके मानस पटल पर अंकित है। हम हरियाणा

के लोग सदैव राष्ट्र निर्माण की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। हमारे वीर जवानों, परिश्रमी किसानों, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और कर्मठ युवाओं ने सदा ही राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है। इसलिए जब भी भारत की प्रगति, सुरक्षा, सम्मान और वैश्विक प्रतिष्ठा की बात होती है, तो हरियाणा का हृदय उससे गहराई से जुड़ जाता है।

पिछले 12 वर्षों में देश ने जिस आत्मविश्वास, स्थिरता और विकास का अनुभव किया है, उसने हरियाणा के जन–जन को भी नई ऊर्जा और नए विश्वास से भर दिया है।" नायब सैनी ने आगे लिखा, "आपने हरियाणा के गांवों में सभी बेघर परिवारों को घर देकर, माताओं–बहनों के घर धुआं रहित रसोई का सपना साकार करके, हर गरीब को बिना भेदभाव के सरकारी सहायता देकर और डिजिटल तकनीक के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर सुशासन की ऐसी छाप छोड़ दी है, जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।" मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा आपकी कर्मभूमि रही है। आपका हरियाणा से विशेष लगाव है। आप 17 बार प्रधानमंत्री के रूप में हरियाणा आए। आपने हर बार अपना पूरा प्यार हम पर लुटाया है। हमें बड़ी–बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। हमारे लिए सबके नाम तो इस पत्र में लिखना संभव नहीं है। आपने अब तक 1,390 किलोमीटर लंबे 22 राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया है। हरियाणा मेहनतकश किसानों की भूमि है। आपने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमें 9,888 करोड़ रुपये देकर जनसेवा की नई मिसाल प्रस्तुत की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 20.17 लाख किसानों को 7,562 करोड़ रुपये दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 15 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। प्रदेश में 2.18 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आयुष्मान भारत–चिरायु योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को 4,148 करोड़ रुपये से मुफ्त इलाज मिला है। पीएम गरीब अन्य कल्याण योजना में 1.57 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.56 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, " किसी भी नेता की पहचान केवल उसके निर्णयों से नहीं होती। बल्कि, उसके व्यक्तित्व, कार्यशैली और मूल्यों से भी होती है। सार्वजनिक जीवन में आपका (प्रधानमंत्री) अनुशासन, अथक परिश्रम, सादगी और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है। आज आप भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुके हैं। हम हरियाणावासी धर्मक्षेत्र–कुरुक्षेत्र की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की कालजयी परंपरा को अक्षरशः पालन करते हुए आपके प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करके स्वयं को और अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

फगवाड़ा–बंगा मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, कारों और मोटरसाइकिल की टक्कर में पिता–पुत्री की मौत, मां गंभीर घायल

फगवाड़ा/बंगा। फगवाड़ा–बंगा मार्ग पर देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फगवाड़ा और बंगा के बीच सड़क पर दो कारों और एक मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार पिता और बेटी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में घायल महिला को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी परमजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुखबीर बादल पर कसेगा एसआईटी का शिकंजा, पूर्व जत्थेदार का दावा– अकाल तख्त में कबूला था बहिबलकलां गोलीकांड का गुनाह

जालंधर। फरीदकोट के चर्चित बहिबलकलां गोलीकांड मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मामले की बारीकी से जांच कर रही विशेष जांच टीम के सामने श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने गुरुवार को अपना अहम बयान दर्ज करवाया है। इस बयान में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, जो पंजाब की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने एसआईटी को दिए बयान में यह बड़ा दावा किया है कि श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपनी पेशी के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने बहिबल गोलीकांड को लेकर अपनी जिम्मेदारी साफ तौर पर स्वीकार की थी। सबसे अहम बात यह है कि सुखबीर बादल का यह कथित कबूलनामा श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष सार्वजनिक रूप से हुआ था और इसकी बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। ज्ञानी रघुबीर सिंह के मुताबिक, यह वीडियो आज भी अकाल तख्त के रिकॉर्ड में पूरी तरह सुरक्षित है। अपने बयान में जत्थेदार ने स्पष्ट किया कि बहिबल कलां में जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, उन निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर एक सोची–समझी साजिश के तहत गोलियां चलवाई गई थीं। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना ने पूरे सिख समुदाय के हृदय को छलनी कर दिया था और उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सिख समुदाय की खातिर इस पूरे मामले में छिपी असली सच्चाई का सामने आना बेहद जरूरी है। सूत्रों की मानें तो पूर्व जत्थेदार के इस सनसनीखेज बयान के बाद एसआईटी की जांच की दिशा बदल सकती है। अब जांच टीम ज्ञानी रघबीर सिंह द्वारा दिए गए बयान और श्री अकाल तख्त में मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग सहित अन्य सभी साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल कर सकती है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि एसआईटी की जांच में इन दावों की पुष्टि हो जाती है, तो सुखबीर सिंह बादल के लिए कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां अचानक से कई गुना बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 2015 को बहिबल कलां में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाओं के विरोध में सिख संगत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने अचानक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह संवेदनशील मामला लंबे समय से पंजाब की सियासत और धार्मिक हलकों में गूंज रहा है। वर्तमान में एसआईटी ने इस केस में कई पुलिस अधिकारियों को चार्जशीट किया हुआ है और चंडीगढ़ जिला अदालत में मामले की सुनवाई लगातार जारी है।

ज्ञानेश कुमार ने चंबा में मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किया प्रोत्साहित

शिमला। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार रविवार को चंबा जिले के खज्जियार स्थित एक मतदान केंद्र पहुंचे और वहां तैनात चुनाव अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बातचीत की।

इस दौरान श्री कुमार ने युवा मतदाताओं से भी संवाद किया और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले वह धर्मशाला गये थे, जहां उन्होंने चुनाव अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची को अद्यतन रखने और उसकी शुद्धता बनाए रखने में बीएलओ की भूमिका की सराहना की। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में नंबर 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है।

मनाली में लगेगा एम डब्ल्यू बी का एआई ट्रेनिंग कैंप

चंडीगढ। मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन (एमडब्ल्यूबीए) का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत मांग पत्र सौंपते हुए राज्य के पत्रकारों को हरियाणा की तर्ज पर पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, दुर्घटना बीमा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन के उत्तर भारत के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने किया। उनके साथ संगठन के महासचिव सुरेंद्र मेहता, कोषाध्यक्ष तरुण कपूर, हिमाचल प्रभारी संजय भूटानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन चोपड़ा तथा संगठन सचिव मेवा सिंह राणा भी मौजूद रहे।साथ में हिमाचल एम डब्ल्यू बी के अध्यक्ष विशाल सूद भी मौजूद रहे।सी एम सुक्खू से एम डबल्यू बी के प्रतिनिधि मंडल को प्रधान मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने मिलवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष पत्रकारों की समस्याओं और उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले पत्रकार समाज और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते हैं। विषम परिस्थितियों में भी पत्रकार जनता तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाएं नहीं मिल पातीं। ऐसे में पत्रकारों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं समय की आवश्यकता हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा प्रदेश में पत्रकारों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, जिनमें पेंशन, चिकित्सा सहायता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के पत्रकार भी लंबे समय से ऐसी ही सुविधाओं की अपेक्षा कर रहे हैं। संगठन ने मांग की कि प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक पत्रकार कल्याण नीति तैयार करे, जिससे राज्य के मीडिया कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में पत्रकारों के कौशल विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी उल्लेख किया। संगठन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश इकाई राज्य के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए मनाली में तीन दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना चाहती है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया जगत तेजी से तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समाचार संकलन, डेटा विश्लेषण, तथ्य जांच, कंटेंट निर्माण तथा डिजिटल मीडिया प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पत्रकारों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना आवश्यक हो गया है। प्रस्तावित प्रशिक्षण शिविर में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को एआई के प्रभावी, जिम्मेदार और नैतिक उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके माध्यम से उन्हें बदलते मीडिया परिवेश के अनुरूप स्वयं को तैयार करने का अवसर मिलेगा। संगठन का मानना है कि तकनीकी रूप से दक्ष पत्रकार अधिक गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के लिए अपनी सुविधानुसार समय और तिथि निर्धारित करें तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। साथ ही मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया।उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है।समय जल्दी सुनिश्चित कर संस्था को अवगत करवाया जाएगा। मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन ने पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की भी घोषणा की है। संगठन ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रस्तावित एआई प्रशिक्षण शिविर के दौरान हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को 10 लाख रुपये तक की निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने की योजना शिमला से शुरू कर दी है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार अक्सर जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं, सामाजिक तनाव और अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में समाचार संकलन के दौरान उन्हें कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में दुर्घटना बीमा जैसी सुविधा उनके और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। यदि यह योजना सफल होती है तो प्रदेश के हजारों पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। संगठन के अनुसार पत्रकारों के कल्याण के लिए भविष्य में स्वास्थ्य सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तथा अन्य कल्याणकारी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इसके लिए सरकार और मीडिया संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि हिमाचल सरकार का रुख सकारात्मक रहा। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पत्रकारों के हितों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं मीडिया की भूमिका को भली–भांति समझते हैं और पत्रकारों के कल्याण से जुड़े विषयों पर संवेदनशील हैं। नरेश चौहान ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि पत्रकारों के हित में प्रस्तुत मांगों का अध्ययन कर उन्हें व्यवहारिक रूप देने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा और उनके पेशेवर विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार सकारात्मक सोच रखती है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही पत्रकारों के लिए ऐसी योजनाओं को लागू करेगी, जिससे उन्हें हरियाणा की तर्ज पर पेंशन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, सोमवार 07 सितंबर 2026 | पृष्ठ-6

घर के अंदर आग से बुरी तरह झुलसी महिला 80 प्रतिशत जला शरीर भुवनेश्वर रेफर

पुरी ०६/०९ (संवाददाता): ओडिशा के पुरी जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई। कुभारपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के डोम साही इलाके में करीब 30 वर्षीय महिला अपने घर के अंदर गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला की पहचान सरोजिनी मल्लिक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से उसका शरीर करीब 80 प्रतिशत तक जल गया। गंभीर हालत में उसे पहले पुरी जिला मुज़्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉज़्टरों ने बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर रेफर कर दिया।

स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना बुधवार रात करीब 8 बजे हुई। आसपास रहने वाले लोगों ने अचानक सरोजिनी के घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही पड़ोसी उसके घर की तरफ दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि महिला आग की लपटों में घिरी हुई थी और उसके कपड़े जल चुके थे। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। पड़ोसियों ने तत्काल महिला को बचाने की कोशिश शुरू की। किसी तरह आग बुझाकर उसे गंभीर हालत में घर से बाहर निकाला गया। इसके बाद बिना समय गंवाए उसे इलाज के लिए पुरी जिला मुज़्यालय अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस चुका था, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर बताई गई।

अस्पताल में डॉज़्टरों ने महिला का प्राथमिक उपचार किया। करीब 80 प्रतिशत तक शरीर झुलसने के कारण डॉज़्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए उच्च चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में ले जाने की सलाह दी।

इसके बाद उसे एज़्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर भेजा गया, जहां उसका आगे का इलाज किया जाना है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के बीच यह सवाल बना हुआ है कि आखिर महिला के घर के अंदर आग कैसे लगी और वह इतनी बुरी तरह इसकी चपेट में कैसे आई। फिलहाल घटना के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आग दुर्घटनावश लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

बताया जा रहा है कि घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने महिला की चीख सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया दी। पड़ोसियों की तत्परता के कारण उसे समय रहते आग की लपटों से बाहर निकाला जा सका और अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि तब तक महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर महिला के परिवार और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा सकती है।

मामले में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि आग लगने के समय महिला घर में अकेली थी या वहां कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। इसके अलावा आग की शुरुआत किस स्थान से हुई और घर में ऐसी कौन सी वस्तु मौजूद थी जिससे आग तेजी से फैल सकती थी, यह भी जांच का विषय है।

महिला के करीब 80 प्रतिशत तक झुलसने की जानकारी ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के इलाज में विशेष चिकित्सा निगरानी की जरूरत होती है। इसी वजह से पुरी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉज़्टरों ने उसे भुवनेश्वर भेजने का निर्णय लिया।

स्थानीय लोगों के अनुसार महिला के घर से अचानक चीखने की आवाज आई थी। पड़ोसी जब अंदर पहुंचे तो उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। लोगों ने तत्काल आग बुझाई और उसे बचाने का प्रयास किया। इसके बाद घायल महिला को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। फिलहाल इस घटना के पीछे किसी तरह की आपराधिक गतिविधि होने की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आग लगने के कारण को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस और संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि महिला किस परिस्थिति में आग की चपेट में आई।कानून प्रवर्तन ऐसे मामलों में घटनास्थल की जांच महत्वपूर्ण होती है। घर के अंदर मौजूद ज्वलनशील पदार्थ, रसोई गैस, बिजली के उपकरण या अन्य संभावित कारणों की जांच से आग लगने की वजह का पता लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा घायल महिला का बयान भी मामले की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए अहम हो सकता है, हालांकि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बयान दर्ज करने की स्थिति उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी। घटना के बाद डोम साही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। स्थानीय लोग महिला की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने चीख सुनते ही महिला की मदद की और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। पुरी जिला मुज़्यालय अस्पताल में डॉज़्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भुवनेश्वर रेफर किया। इसके बाद एज़्बुलेंस के जरिए उसे वहां ले जाया गया। अब डॉज़्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। घटना ने एक बार फिर घरों में आग से सुरक्षा को लेकर सतर्कता की जरूरत को सामने रखा है। रसोई गैस, बिजली के उपकरण और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का इस्तेमाल करते समय सावधानी बेहद जरूरी है। हालांकि सरोजिनी के मामले में आग किस कारण लगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है और आधिकारिक जांच के बाद ही इसकी सही वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता गंभीर रूप से घायल सरोजिनी मल्लिक के स्वास्थ्य को लेकर है।

करीब 80 प्रतिशत शरीर झुलसने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। दूसरी ओर घटना के कारणों को लेकर स्थानीय स्तर पर कई सवाल बने हुए हैं। जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि बुधवार रात डोम साही स्थित घर के अंदर आखिर ज़्या हुआ था।

झारखंड के मरीज़ ने आईजीएच में आपातकालीन सर्जरी और लंबे समय तक गंभीर देखभाल के बाद की रिकवरी

राउरकेला ०६/०९ (संवाददाता): झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के गुआ माइन्स के रहने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति ने सेल के राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात जनरल हॉस्पिटल (आईजीएच) में आपातकालीन पेट की सर्जरी और लंबे समय तक गंभीर देखभाल के बाद रिकवरी की है। गुआ माइन्स के निवासी श्री पचाय केराई को पेट में गंभीर समस्या (पेप्टिक परफोरेशन) के कारण ढ्ल॥ में भर्ती कराया गया था, जिससे पेट के अंदर गंभीर संक्रमण हो गया था। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज पाणिग्रही के सहयोग से, मुज़्य सलाहकार डॉ. जे. आर. साहू और अतिरिक्त मुज़्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार प्रधान की देखरेख में उनकी इमरजेंसी एज़्सप्लोरेटरी एज़्डोमिनल सर्जरी की गई।

सर्जरी के बाद, रोगी ने पेट के संक्रमण के लिए एक और गंभीर श्वसन विफलता (एआरडीएस) विकसित की और आईसीयू में 12 दिनों के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता थी। उनकी स्थिति को करीबी निगरानी, लगातार ज़्लड-गैस आकलन और रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए उचित दवा के माध्यम से प्रबंधित किया गया था।

एनेस्थीसिया सपोर्ट अतिरिक्त मुज़्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोरंजन सामंतराय और एनेस्थीसिया सलाहकार डॉ. सी. के. कासी ने दिया। मरीज़ को आईसीयू और एनेस्थीसिया विभाग की प्रभारी डॉ. संजुक्ता पाणिग्रही और डॉ. अनीता लाकरा की देखरेख में, नर्सिंग टीम के सहयोग से समर्पित गंभीर देखभाल दी गई।

अपने फेफड़ों की कार्यक्षमता में धीरे-धीरे सुधार के साथ, मरीज़ को सफलतापूर्वक यांत्रिक वेंटिलेशन से हटाया गया और बाद में वार्ड में शिज़्ट कर दिया गया। अब वे मुंह से खाना ले रहे हैं, अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं और स्थिर स्थिति में उन्हें डिस्चार्ज करने की योजना है।

मरीज़ की सफल रिकवरी समय पर सर्जरी, विशेष गंभीर देखभाल और आईजीएच में सर्जरी, एनेस्थीसिया, आईसीयू और नर्सिंग टीमों के समन्वित प्रयासों के महत्व को उजागर करती है। यह मामला जटिल और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी में क्रिटिकल केयर सपोर्ट सहित व्यापक, समय पर और मरीज़-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आईजीएच की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ओडिशा के स्कूल में शिक्षक के तबादले को लेकर विरोध प्रदर्शन

ज़्योंझर ०६/०९ (संवाददाता): जिले के आनंदपुर उपखंड स्थित बांचो उच्च प्राथमिक (यूपी) स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण के बाद मंगलवार को स्कूल के बाहर अभिभावकों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल समुदाय ने स्थानांतरण पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और स्कूल के विकास में प्रधानाध्यापक के योगदान पर प्रकाश डाला। सूत्रों के अनुसार, मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के प्रावधान में अनियमितताओं और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण का कारण बताया गया। अभिभावकों और छात्रों ने अधिकारियों से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की, और कहा कि प्रधानाध्यापक ने स्थानीय समुदाय का सज़्मान और विश्वास अर्जित किया है। प्रदर्शनकारी स्कूल के सामने इकट्ठा हुए, हाथों में तज़्तियाँ लिए और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए नारे लगाए। प्रशासन ने अभी तक विरोध प्रदर्शन या स्थानांतरण की समीक्षा के किसी भी निर्णय के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। एक छात्र की माँ, पद्मावती बराल ने कहा, टुकू सर (प्रधानाध्यापक) ने ज़्या किया? अगर शिक्षकों को स्थानांतरित करना है, तो सभी का तबादला किया जाएगा। वरना, किसी भी शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। पद्मावती ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि स्कूल शांतिपूर्वक चले और सभी शिक्षक यहीं रहें।

ओडिशा ने बार-बार नियम तोड़ने वालों का पीयूसीसी जुर्माना घटाया

भुवनेश्वर ०६/०९ (संवाददाता): ओडिशा सरकार ने बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के चलने वाले वाहनों पर लगने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने को 10,000 रुपये से घटाकर 6,000 रुपये कर दिया है। यह जानकारी कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विभूति भूषण जेना ने दी। जुर्माने के नए नियमों के तहत, मोटरसाइकिल और तीन-पहिया वाहनों पर पहली बार गलती करने पर 1,000 रुपये और उसके बाद की गलतियों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मोटर कैब, कार, जीप और ट्रैज़्टर/ट्रेलर पर क्रमश: 2,000 रुपये और 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जिन ट्रांसपोर्ट वाहनों को इन कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, उन पर पहली बार गलती करने पर 3,000 रुपये और उसके बाद की गलतियों पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।सरकार ने 2019 में लागू किए गए ज़्यादा जुर्माने के बारे में वाहन मालिकों, वाहन एसोसिएशन और मीडिया से मिली प्रतिक्रिया के बाद जुर्माने की रकम में बदलाव किया है। इस कदम का मकसद मोटर व्हीकल एज़्ट के तहत नियमों का पालन सुनिश्चित करना और साथ ही लोगों के लिए नियमों को मानना आसान बनाना है। जेना ने कहा कि प्रदूषण और इंश्योरेंस से जुड़े नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को चेकिंग तेज़ करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि वाहनों के पास वैलिड क्ष्ट और इंश्योरेंस के कागज़ात हों। जेना ने कहा कि जिन वाहनों के ई-चालान 90 दिनों से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं, वे PUCC रिन्यूअल के लिए योग्य नहीं होंगे।

पुलिस ने कंधमाल के जंगल में दो माओवादियों को मार गिराया

कंधमाल ०६/०९ (संवाददाता): ओडिशा पुलिस ने को कंधमाल जिले में दो माओवादियों को मार गिराया और उनके शिविर से हथियार और गोला-बारूद जज़्त किया। मृतकों की पहचान पड़ोसी छज़ीसगढ़ के मूल निवासी मनकू और चंदन के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित सीपीआई-माओवादी संगठन के कालाहांडी-कंधमाल-बौध-नयागढ़ (केकेबीएन) डिवीजन के सदस्य थे। कंधमाल एसपी हरीशा बीसी ने बताया कि दोनों माओवादियों के शव बरामद करने के अलावा सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से एक राइफल, रिवॉल्वर, कारतूस, वॉकी-टॉकी सेट, बैटरी और अन्य सामान जज़्त किया है। एसपी ने कहा कि कंधमाल-कालाहांडी सीमा पर बालीगुडा पुलिस सीमा के भीतर पुरंजीबा रिजर्व वन में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों से जिला स्वैच्छिक बल (डीवीएफ) और एसओजी जवानों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा, आज दोपहर के समय सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षाकर्मियों को देखते ही माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। इसके बाद हुई गोलीबारी में दो माओवादी मारे गए। मनकू केकेबीएन डिवीजन में एरिया कमेटी मेंबर (एसीएम) के पद पर कार्यरत था। चंदन कंधमाल जिले में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन का सदस्य था। एसपी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया है कि इलाके में कोई और माओवादी मौजूद न हो। मुठभेड़ के बाद डीजीपी वाईबी खुरानिया ने कंधमाल एसपी और डीवीएफ टीम को सफलता के लिए बधाई दी। सूत्रों ने बताया कि छज़ीसगढ़ में नज़्सल विरोधी अभियान तेज होने के साथ ही माओवादी ओडिशा के जंगलों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।

आरएसपी के विभिन्न जोनों में आगामी राजभाषा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में प्रश्नोज़री प्रतियोगिताओं का आयोजन

राउरकेला ०६/०९ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र में आगामी 'राजभाषा पखवाड़ा' के आयोजन के क्रम में कर्मचारियों के बीच जोनवार प्रश्नोज़री प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। चार अलग-अलग स्थानों पर आयोजित चार जोनों की प्रश्नोज़री प्रतियोगिताओं में लगभग 150 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जोन-2 के अंतर्गत विज़ एवं लेखा (एफ.एंड ए.) विभाग के 28 कर्मचारियों ने विज़ एवं लेखा सज़्मेलन कक्ष में आयोजित प्रश्नोज़री प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर मुज़्य महा प्रबंधक प्रभारी (विज़म एवं लेखा) तथा अतिरिक्तन प्रभार कार्यपालक निदेशक (विज़् एवं लेखा), श्री राजेश दासगुप्ता तथा मुज़्यर महा प्रबंधक (विज़ा एवं लेखा), श्री बसंत सिंह, हिंदी अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जोन-13 के अंतर्गत डिजाइन, शॉप्स, ए.सी., कज़्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग तथा रिपेयर शॉप इलैज़्ट्रिकल विभागों के 72 कर्मचारियों ने रिपेयर शॉप (मेकानिकल) के सज़्मेलन कक्ष में आयोजित प्रश्नोज़री प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर महा प्रबंधक प्रभारी (शॉप्स), श्री डी.के.नायक तथा संबंधित विभागों के हिंदी अधिकारी उपस्थित थे। इसी प्रकार, जोन-4 के अंतर्गत एच.आर. (वर्क्स एवं नॉन-वर्क्स तथा ज्ञानार्जन एवं विकास) के 24 कर्मचारियों ने ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर महा प्रबंधक प्रभारी (वर्क्स), श्री संजय मेहरोत्रा एवं हिंदी अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि ज्ञानार्जन एवं विकास में आयोजित यह प्रतियोगिता पहली बार ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। इसी दिन की अंतिम प्रतियोगिता पी.डी. सज़्मेलन कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें पावर डिस्ट्रीज़्यूशन एवं सी.पी.पी.-1 के 17 कर्मचारियों ने भाग लिया। आर.एम.एच.पी. सज़्मेलन कक्ष में 3 सितंबर को आयोजित प्रश्नोज़री प्रतियोगिता में आर.एम.एच.पी. के 21 कर्मचारियों ने भाग लिया। मुज़्य महाप्रबंधक (आर.एम.एच.पी.), श्री शेखर नारायण ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसी दिन अग्निशमन सेवाएँ एवं सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा सज़्मेलन कक्ष में इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रश्नोज़री प्रतियोगिता में 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। संबंधित विभागों के हिंदी अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बाद में उसी दिन ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में एक अन्य प्रश्नोज़री प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें आर.सी.एम., ट्रांसपोर्ट, एफ.एम.एम., एम.एस.एस., बी.ई. एवं आई.ई.डी., क्रेन मेंटिनेंस तथा टी. एंड आर.एम. के 27 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। इसके पश्चात विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबोधित किया तथा राजभाषा संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी। प्रतियोगिताओं का संचालन उप प्रबंधक (जन संपर्क-राजभाषा), श्री अनिल झा एवं अनुभाग अधिकारी (राजभाषा), श्री शिबाशिष पटनायक ने किया। उल्लेखनीय है कि अधिक से अधिक विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टाउनशिप एवं चिकित्सा सेवाओं सहित पूरे संयंत्र को 24 जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले एक समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का समन्वय जनसंपर्क-राजभाषा इकाई द्वारा संबंधित विभागों के हिंदी अधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा है।

AFFIDAVIT

I, SANUJ KUMAR BEHERA aged about 44 years Son of Late Ulla Behera, resident of House No-LCR/62, Chhend Colony, ph-I, Rkl-15, P.S.Chhend, Dist-Sundargarh, Odisha-769015 declare by this affidavit No-A/20, dated:6/8/2026, that now onwards I shall be known as SANUJ KUMAR BEHERA for all future purposes.